

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा  
2. प्रकरण संख्या : 137/2020  
3. उमवान : सरकार जरिये, थानाधिकारी, थाना-कोटपूतली

बनाम

1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री गणपतराम निवासी ढाणी झाडवाली तन भौणावास थाना प्रागपुरा।  
2. किशन पुत्र श्री बंशीधर निवासी ढाणी बौरावाली तन टसकोला थाना प्रागपुरा।
4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022  
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।  
ब) श्री विवेक असवाल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना कोटपूतली, जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 30.07.2011 को पुलिस थाना कोटपूतली द्वारा वाहन (पिकअप) नं. RJ-32-GA-5570 से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहे 12 प्लास्टिक व 2 लोहे के कुल 14 ड्रम मय 1750 लीटर डीजल व दो लोहे के ड्रम मय 300 लीटर पेट्रोल को मय पिकअप जब्त किया। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल खरीदने के बिल पेश नहीं किये गये एवं निर्धारित मात्रा से अधिक का भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल-पेट्रोल के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही डीजल-पेट्रोल के खरीद-फरोख्त का लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर नवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। दिनांक 18.05.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री विवेक असवाल ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया। दिनांक 29.08.2011 को श्री अनिल कुमार यादव ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,50,000/- का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 20.09.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक जवाब हेतु नियत रहने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। इस दौरान बार-बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 30.07.2011 को जब्त डीजल-पेट्रोल का अवैध रूप से भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त डीजल-पेट्रोल के बिल नहीं दिये तथा डीजल-पेट्रोल की खरीद बेचान का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 में किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञापित के एक समय पर उसके पास अधिसूचित सीमा यथा 1000 लीटर से अधिक डीजल की मात्रा का स्वयं या अपने निमित्त किसी भी व्यक्ति के मार्फत किसी भी समय भण्डारण करने और कब्जे में रखने के संबंध में प्रतिबंध व निर्बन्धन है तथा बिना अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल व डीजल का बेचान प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब एवं कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 12 प्लास्टिक व 2 लोहे के कुल 14 ड्रम मय 1750 लीटर डीजल व दो लोहे के ड्रम मय 300 लीटर पेट्रोल एवं जब्त वाहन पिकअप नंबर RJ-32-GA-5570 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार शर्मा)  
अतिरिक्त कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर।